विकास

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सिटी बनाने के लिए दुनियाभर की कंपनियों से मांगा टेंडर

एआई सिटी में डाटा सेंटर, ग्रीन टावर पर फोकस

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी में बनने वाली देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सिटी (एआई सिटी) की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है। इसे बनाने के लिए दुनियाभर की कंपनियों से टेंडर मांगा गया है। न्यूनतम एक हजार करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी ही इसमें हिस्सा ले सकेगी।

नादरगंज में 40 एकड़ में विकसित होने वाली एआई सिटी में ग्रीन टावर, एआई सेंटर व डाटा सेंटर पर खास फोकस किया गया है। एआई सिटी में कम से कम 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा।

एआई सिटी में कम से कम 20 हजार करोड़ रुपये का होगा निवेश

कानपुर-लखनऊ रोड पर अमौसी के पास 40 एकड़ जमीन पर एआई सिटी तैयार करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसे यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत बनाया जा रहा है। डवलपर को एआई सिटी की डिजाइन, डवलपमेंट और संचालन का जिम्मा दिया जाएगा।

यूपी को अगले चार सालों में दस खरब की अर्थव्यवस्था बनाने में एआई सिटी की बड़ी भूमिका होगी।

आईटी ईको सिस्टम में यूपी का देश में छठा और सबसे ज्यादा स्टार्टअप में पहला स्थान है। आईटी इंडस्ट्री में शीर्ष तीन में आने से निवेश की रफ्तार बढ़ेगी। एआई के बिना आईटी सेक्टर में तरक्की संभव नहीं है। लखनऊ में पहले से 800 से ज्यादा तकनीकी आधारित इंडस्ट्री और लगभग 200 टेक स्टार्टअप हैं। एचसीएल और टीसीएस की मौजूदगी, आईआईटी कानपुर, एचबीटीयू, ट्रिपलआईटी लखनऊ का एआई सिटी में अहम योगदान होगा।

सस्ते ऑफिस मिल जाएंगे

लखनऊ की एआई सिटी में नोएडा, गुड़गांव और हैदराबाद की तुलना में 50 फीसदी तक सस्ते ऑफिस होंगे। इसे देश के इनोवेशन हब के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहां केवल टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए प्लग एंड प्ले सिस्टम विकसित किया जाएगा। यानी उद्यमी केवल आएं और काम शुरू कर दें।

विश्वस्तरीय आवासीय परिसर होगा

परिसर में विश्वस्तरीय आवासीय परिसर बनाया जाएगा। रिक्रिएशन सेंटर, फिटनेस सेंटर व इंजीनियरिंग संस्थान आदि सभी कुछ एआई सिटी में होंगे। इसके लिए डवलपर को 40 एकड़ जमीन निशुल्क दी जाएगी। आईटी पार्क के लिए 25 फीसदी पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 20 करोड़ रुपये है। आईटी सिटी के लिए 100 करोड़ और स्टांप शुल्क में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। संचालन संबंधी खर्च में 20 करोड़ सरकार देगी।